भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–05 जनवरी, 2019

कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के ही ढर्रे पर जन दमनकारी नीतियां बेरोकटोक जारी!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी राज्य की तमाम उत्पीड़ित व आदिवासी जनता सहित प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों से अपील करती है कि वे विगत की भाजपा सरकार के ही ढर्रे पर कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोकटोक जारी जन दमनकारी नीतियों के विरोध में आवाज बुलंद करें.

सत्ता संभालते ही कांग्रेस पार्टी व नई सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने यह कह दिया कि माओवाद की समस्या एक राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्या है, इसके हल के लिए पीड़ितों, आदिवासियों, पुलिस, सामाजिक प्रमुखों व बुद्धिजीवियों के साथ वार्ता की जाएगी. यह एक भ्रामक, धोखेबाजीपूर्ण व साजिशाना ऐलान है. क्योंकि साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि माओवादियों के साथ कोई बात नहीं होगी. इससे यह साफ और सुस्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, आदिवासी हितैषियों को भ्रमित करना चाहती है. वह हम पर हिंसावादी व विकास विरोधी होने का आरोप/ठप्पा लगाकर दमन में बढ़ोत्तरी करना चाहती है. सामाजिक प्रमुखों व बुद्धिजीवियों से वार्ता के नाम पर पिछली सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ व जनता के पक्ष में डटे रहे जनपक्षधर, जनवादी–प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को जन आंदोलनों से दूर करने की साजिश रच रही है.

इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए चुनावी घोषणा पत्र के कुछेक लोकलुभावन वादों को कई विसंगतियों व लीपापोतियों के साथ अमल करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित व आकर्षित करके रखना चाहती है जिसका भंडाफोड़ करना आवश्यक है. विशेषकर वह गरीबी उन्मूलन व जल–जंगल–जमीन पर जनता के अधिकार को सुनिश्चित करने संबंधी योजनाओं व वादों को छोड़, बाकी नीतिगत मामलों पर अमल की घोषणाएं ज्यादा कर रही है. सत्तासीन होने के पहले तक कांग्रेस जिन नरसंहारों, झूठी मुठभेड़ों, महिलाओं पर अत्याचारों, बलात्कारों व उनकी हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाती रही, उन पर कोई न्यायिक जांच का ऐलान नहीं किया. लोहंडीगुडा के टाटा विस्थापितों को जमीन वापस करने की कांग्रेस सरकार की घोषणा अवश्य स्वागतेय है, लेकिन यह मजबूरन लिया गया निर्णय है क्योंकि वहां की वीर जनता ने 10 साल के जबर्दस्त संघर्ष के जरिए टाटा को पहले ही (अक्तूबर, 2015) बोरिया–बिस्तर बांध कर भागने मजबूर किया था और जमीन वापस पाने आंदोलनरत थी जिसका कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था.

प्रशासनिक फेरबदल के पहले ही दौर में राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त डीएम अवस्थी जो पूर्व में नक्सल ऑपरेशंस के विशेष डीजी थे और नुल्कातोंग जघन्य नरसंहार के सूत्रधार थे, ने यह घोषणा की कि माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस यथावत जारी रहेंगे और सरकार आगे की रणनीति बनाने में लगी है. इतना ही नहीं, जिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ विपक्ष में रहते कांग्रेस ने मोर्चा खोला था, उसी को पुलिस विभाग की लूप लाइन से उठाकर कांग्रेस सरकार ने आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के आईजी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाया है. ये कदम भविष्य में बढ़ने वाले दमन के स्वाभाविक संकेत ही हैं.

भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर को पदभार संभालने के पहले की ही तरह बाद में भी हमारी पार्टी एवं संघर्षरत जनता के खिलाफ पुलिस आपरेशंस बेरोकटोक जारी हैं. 17 दिसंबर को ही नारायणपुर के ओरछा से अंदरूनी गश्त पर निकली एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने कुडमेर गांव के 4 ग्रामीणों को ईनामी माओवादियों के नाम पर गिरफ्तार किया था. 20 दिसंबर को कांकेर जिले के चारगांव इलाके के माटियाखार के पास हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस बलों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी करके एक साथी को घायल किया गया एवं एक और साथी सहित दो ग्रामीणों को पकड़कर अवैध रूप से पुलिस कब्जे में रखा गया है. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अर्बन माओइस्ट के नाम पर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के तर्ज पर ही 22 दिसंबर को छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र की सरहदी बाग नदी के पास एक केंद्रीय संस्थान में कार्यरत सीनियर टेक्नीशयन एन. वेंकट राव को अर्बन माओइस्ट के नाम पर जबरन गिरफ्तार किया गया है. 23 तारीख को माड के भट्टुवेडा में ग्रामीणों पर फायरिंग की गयी. 27 दिसंबर को गश्त पर आयी पुलिस ने बीजापुर जिले के बासागुडा के पास से 5 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया. 2 जनवरी को

बीजापुर जिले के नाडिगांव के 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह एक तरफ यह कहते हुए कि बंदूकों से माओवादी समस्या का हल नहीं हो सकता है, दूसरी ओर गश्त अभियानों, मुठभेड़ों, अवैध गिरफ्तारियों को बेरोकटोक जारी रखना कांग्रेस की नयी सरकार की कपटतापूर्ण नीति व दोगलेपन को ही दर्शाता है जिस पर गौर करने व हर संभव तरीके में विरोध करने हमारी पार्टी प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मानवाधिकार संगठनों व आदिवासी , गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों से अपील करती है.

आएं! एक बार जरा नजर डालकर यह देखें कि

देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के साथ किए गए तमाम खनन व औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित समझौतों को रद्द करके संसाधनों की बेरोकटोक लूट को बंद करने;

देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की नीतियों के अमल के लिए आदिवासी बहुल बस्तर सहित तमाम संघर्ष इलाकों में तैनात अर्ध–सैनिक बलों, अतिरिक्त बलों समेत कॉरपेट सेक्युरिटी के कैंपों को हटाने;

नरसंहारों, झूठी मुठभेड़ों के मामलों में स्वतंत्र न्यायिक जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने;

डीआरजी, एसटीएफ, ब्लैक पैंथर्स सह तमाम हत्यारे कमांडो बलों को रद्द करने;

गश्त अभियानों, गांवों पर हमलों, अंधाधुंध गिरफ्तारियों एवं हमारे कार्यकर्ताओं व जनता पर अंधाधुंध गोलीबारी को तुरंत रोकने व दमन योजना 'समाधान' को बंद करके जनवादी–प्रगतिशील व मानवाधिकार संगठनों को स्वेच्छा से काम करने के जनवादी माहौल एवं जनवादी अधिकारों को बहाल करने,;

जेलों में बंद विस्थापन विरोधी, मानवाधिकार, जनवादी, क्रांतिकारी आंदोलनों के कार्यकर्ताओं व नेताओं सहित आम जनता को तुरंत व निशर्त रिहा करने;

राज्य के 54 विभागों में कार्यरत सभी संविदा, अनियमित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों व शिक्षाकर्मियों को संविलयन, समान वेतनमान सहित स्थायी नियुक्तियां देने;

आउट सोर्सिंग बंद करके सभी रिक्त पदों को स्थानीय बेरोजगारों से भरने;

किसानों की तमाम फसलों के लागत खर्च के दोगुना समर्थन मूल्य देने व आदिवासियों के वनोपजों के लिए उचित व पर्याप्त समर्थन मूल्य देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने;

भाजपा के शासनकाल में दमन के शिकार आदिवासी अवाम के पक्ष में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों पर लगाए गए झूठे केसों को वापस लेने;

बैलाडीला से कच्चा माल व सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर बंद पड़े स्पंज आइरन व री–रोलिंग मिलों को चालू करवाकर स्थायी नियुक्तियों के साथ छंटनीशुदा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं अन्य

उपरोक्त मांगों व समस्याओं में से किसी एक के बारे में भी कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की जोकि यह दर्शाता है कि वह अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ही नीतियों पर अमल करने वाली है, भले ही योजनाओं, नीतियों के नाम क्यों न बदल दिए जाते हों.

हमारी पार्टी राज्य की उत्पीड़ित जन समुदायों का आह्वान करती है कि वे अपनी तमाम जायज मांगों के हल के लिए जनांदोलनों का दबाव बनाकर कांग्रेस सरकार को उन्हें पूरा करने बाध्य करें. कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेखित सभी वादों की पूर्ति के लिए संबंधित तबकों के लोग गोलबंद होकर खुले व कानूनी जन संघर्षों व जन प्रतिरोध को व्यापक पैमाने पर संचालित करें.

विकल्प

(विकल्प)

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)